Absence of SCs in Arunachal Pradesh

1370. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the letter written to his Ministry by Government of Arunachal Pradesh in 1989, there is no schedule caste in the State of Arunachal-Pradesh; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESARI): (a) Yes Sir,

(b) The details cannot be disclosed in the Pubblic interest.

राजभर/भर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

1871. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभर/भर जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अनुसार अनुसुचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भर/राजभर विमुक्ति जाति को अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के संबंध में सरकार को भारतीय राजभर महासभा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) सरकार को भारतीय राजभर महासभा से उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुची में शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और अधिक ब्यौरे लोकहित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

डा० गोपालसिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना

1872. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए नियुक्त की गई डा० गोपाल सिंह समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) इस समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त पेनल की रिपोर्ट 24 अगस्त, 1990 को राज्य सभा पटल पर रख दी गई थी। अल्पसंख्यकों से संबंधित सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत विवरण में दे दिया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

15-Point Programme for Minorities

1873. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 15-Point programme announced by the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi for the minorities has been withdrawn;

(b) if not, what is the present status of the scheme;

(c) whether Government will give this programme the status of 20-point programme; and

(d) what has been the benefit to the minorities from this programme during the last 10 years?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESARI): (a) and (b) No Sir. The programme continues to be implemented.

(c) There is no such proposal.

(d) The programme seeks to ensure that a feeling of security is instilled in the minds of the minorities. A statement indicating the benefits flowing from the 15-Point Programme is laid on the Table of the House.

Statement

Details of the Benefits to the Minorities from the 15-Point Programme

COMMUNAL HARMONY

Comprehensive guidelines on promotion of communal harmony have been issued to all State Govts/UT Admns., in April, 1990 with regard to posting of District-officials in communally sensitive areas; rewarding District and Police Officials for good work; and action against persons inciting communal tension or taking part in violance.

SPECIAL COURTS:

All State Govts|UT Admns., have been requested to set up Special Courts to try communal offences at places wherever large scale violance occured. Such courts have already been constituted at Delhi, Meerut, Bhagalpur, Kota and Jaipur.

EX-GRATIA RELIEF TO RIOT VICTIMS:

Guidelines have been issued to state Govts. on revising the amount of Ex-gratia grants in cases of Death/permanent incapacitation from Rs. 20,000 to Rs. 50,000/- and on pension of Rs. 500/ per month to widows of riot victims with no income.

RECRUITMENT

State Govts., have been requested to ensure better representation of minorities in State Police Force; raising of composite batallions and special training programme for Police forces.

EDUCATION:

1. All the 41 minority concentration districts have been covered under the Scheme of Community Polytechnic.

2. UGC Coaching Scheme for minorities is under implementation in 20 Universities and 33 Colleges.

3. 36 Coaching Centres were sanctioned grant-in-aid during 1990-91 under the Pre-examination Training Scheme for candidates belonging to minorities.

HANDICRAFTS: Under the package programme for Handicrafts in minority concentration Districts/areas Craft Development Centres have been set up at Agra (Marble in lay/stonework) Hyderabad (Bidri work), and Howrah (chickan work) during 1990-91. A plant for Metal Handierafts Training Centre is functioning at Moradabad. Design Development Project for wood carving has been launched at Saharanpur.

HANDLOOM:

The Distrcits of Cannore and Calicut of Kerala and Sonitpur in Nadia (West Bengal) have been covered under the package programme for Handloom Development in minority concentration Districts. The District of Murshidabad is proposed to be covered under this programme.

SMALL SCALE INDUSTRY:

1. Common facility centres'proto type Development Centres for lock, leather suit-cases and needle making industries have been set up at Howrah and Aligarh.

2. Training is imparted to entrepreneurs under District Industry Centres. 6051 persons have been trained under Entrepreneurship Development Programme and Self employment Scheme for UN-employed Educated Youth. Training is also imparted to artisans under TRYSEM. 6888 minority artisans have been trained during January, 1990 to September, 1991.

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES:

Funds amounting to Rs. 30.17 crores have been provided to all States Khari & Village Industry Boards for implementing special programmes for rural artisans amongst minorities.

CREDIT SUPPORT:

For availability of credit, 213 branches have been opened in minority concentration districts and 198 additional centres have been identified.

REDRESSAL OF GRIEVANCES:

Instructions have been issued to all State Govts/UT Admns. for taking steps to deal with problems relating to encroachment of WAKF properties/graveyards etc. for redressal of grivances on an expeditious and satisfactory basis.

वक्फ की सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जा

1874. **डा. अबरार अहमद :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वक्फ की सम्पत्तियों पर तेजी से नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं और सरकार ऐसे कब्जों को हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ख) वक्फ की ऐसी सम्पत्तियों और भूमि का ब्यौरा क्या है जो कि मंत्रालयों सहित केन्द्रीय सरकार, इसके विभागों और इसके निकायों के कब्जे में है और जिनका नाममात्र का किराया दिया जाता है अथवा वह भी नहीं दिया जाता है;

(ग) राजस्थान में वक्फ की कितनी सम्पत्ति राजस्थान सरकार अथवा इसके विभागों के कब्जे में है और उसका कितना-कितना किराया कब से बाकी है तथा उसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र ही एक विधान बनाना चाहती है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना

1875. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी/** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) से (ग) जी, हां। यह मामला विचाराधीन है।